(ग) क्या उपरोक्त सहायता में वृद्धि हो रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां। तथापि, यूनियन को नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया कहा जाता है, न कि इण्डियन नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ।

(ख) यूनियन को केवल 1964-65 में 'कोआपरेटिव लीग आफ दी यू० एस० ए०' से उनके नई दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से 44,691.99 रुपये और 1965-66 तथा 1966-67 में 'एशिया फाउंडेशन' से क्रमशः 4,614 रुपये तथा 15,000 रुपये प्राप्त हुए थे।

(ग) यूनियन को 1965-66 से 'कोआपरेटिव लीग आफ यू० एस० ए०' और 1967-68 के प्रारम्भ से 'एशिया फाउंडेशन' से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। इस अवधि में, यूनियन को किसी भी अन्य विदेशी अधिकरण से विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

ग्रामीण जनता को सहकारी आन्दोलन का लाभ

4049. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी आन्दोलन से ग्रामीण जनता को किस हद तक लाभ पहुंचा है ;

(ख) भूमिहीन मजदूरों को सहकारी खेती से किस हद तक लाभ पहुंचा है; और

(ग) भूमिहीन मजदूरों के लाभार्थ तथा उनकी ऋण और पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार क्या योजनाएं बनाने का विचार रखती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सहकारी आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में, ऋण देने, कृषि उपज के विपणन तथा विधायन, कृषि आदानों की सप्लाई, उपभोज्य वस्तुओं के वितरण और डेरी, कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन तथा श्रम ठेका समितियों के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । 1966-67 में सहकारी समितियों ने 35 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को अपने अन्तर्गत ले लिया है और कृषि उत्पादन के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए का ऋण दिया है । उसी वर्ष उन्होंने 335 करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि उपज का विपणन किया और 165 करोड़ रुपए के मूल्य के कृषि आदान तथा 245 करोड़ रुपए के मूल्य की उपभोज्य वस्तुएं वितरित कीं ।

(ख) और (ग). सरकारी बेकार भूमि को बसाने में राज्य सरकारें आम तौर पर उन सहकारी खेती समितियों को प्राथमिकता देती है, जिनमें अधिकतर भूमिहीन श्रमिक होते हैं । तीसरी योजना अवधि में, सरकारी बेकार भूमि पर 1840 सहकारी खेती समितियां गठित की गई थीं । खेती समितियों को अंशपूंजी तथा गोदामों व ढोरशालाओं के लिए ऋण के रुप में वित्तीय सहायता दी जाती है । भूमिहीन श्रमिक, श्रम ठेका तथा निर्माण सहकारी समितियों और अन्य सहकारी समितियों, जैसे डेरी, कुक्कुट पालन, पशुओं की सहकारी समितियां, जिन्हें भी सरकार सहायता देती है, का लाभ भी उठा सकते हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में दक्ष तथा अदक्ष मजदूर

4050. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची और बरौनी में केन्द्र द्वारा नियंत्रित औद्योगिक संस्थाओं में कुल कितने दक्ष तथा अदक्ष मजदूर हैं और इनमें से बिहार राज्य के कितने हैं ;

(ख) क्या बिहार में केन्द्र द्वारा नियंत्रित संस्थानों में नई नियुक्तियों के बारे में समान योग्यताओं के आधार पर बिहार के प्रतिभा-

शाली व्यक्तियों को अधिमान दिया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी नियुक्तियों के मामले म बिहार की उपेक्षा की जाती है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) (क) जानकारी, जिस रूप में मांगी गई है, तत्काल उपलब्ध नहीं है । फिर भी, बरौनी के तेलशोध कारखाने के 2,175 नियमित और अधिकांश मस्टर रोल के कर्मचारियों में से 1,678 कर्मचारी बिहार के हैं । रांची के भारी इन्जीनियरिंग निगम के तीसरी और चौथी श्रेणी के 13,823 कर्मचारियों में से 10,742 कर्मचारी बिहार राज्य के हैं ।

(ख) सरकार की भर्ती सम्बन्धी मौजूदा नीति के अनुसार श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों की भर्ती, जहां तक सम्भव हो, स्थानीय उम्मीदवारों द्वारा की जाती है । श्रेणी तीन और चार के अतिरिक्त अन्य पदों अथवा उनके समान वेतन क्रम वाले पदों पर नियुक्ति, अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन के द्वारा की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

CO-OPERATIVE FARMING SCHEMES IN ORISSA

4051. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Orissa Government had been asked to set up an advisory panel for the promotion of co-operative farming schemes in the state;

(b) if so, the action taken by the State Government in the matter; and

(c) the progress achieved in promoting the co-operative farming schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government constituted the State Cooperative Farming Advisory Board on 18-4-1961, besides the Standing Committee on Cooperative Farming constituted by the Orissa State Cooperative Council on 23-1-1961. The Advisory Board was subsequently dissolved, but the Standing Committee has been continued.

(c) 138 cooperative farming societies have so far been organised in Orissa with a membership of 3,974 and area of 11,054 acres.

MINOR IRRIGATION PROJECTS IN U.P.

4052. SHRI R. R. SINGH DEO : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the number of minor irrigation schemes which were proposed to be taken up by the Central Government during the Third Plan period in U.P.;

(b) the names of schemes on which the work was taken;

(c) the names of schemes on which the work was taken up and suspended due to emergency and other reasons; and

(d) the names of schemes on which work was taken up and later on dropped ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) and (b). The implementation of the minor irrigation schemes is the responsibility of the State Governments themselves. However, to enable the State Governments to implement their minor irrigation programmes, Central assistance in the form of loans and grants was given to them during the Third Five Year Plan period.